4,800 से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी एमडी और एमएस की पोस्टग्रेजुएट (पीजी) की आगामी सत्र में। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सीटों में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही सीटों की संख्या 36,192 हो जाएगी।

बजट सत्र में कटौती नहीं, तीन तक चलेगी संसद

संसदीय दल की बैठक ▸ प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा, अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं

कोरोना वायरस से निपटने में मोदी ने चिकित्सा कर्मियों व मीडिया को सराहा

संसद भवन में मंगलवार को भाजपा की संसदीय दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा सांसदों से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। साथ ही स्पष्ट किया कि संसद के बजट सत्र में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने उन चंद सांसदों के प्रति निराशा व्यक्त की जो कोरोना संक्रमण के चलते मौजूदा सत्र में कटौती करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती सामने हैं, तब सांसदों को अपना काम करते दिखना चाहिए।

बैठक में प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि शनिवार एवं रविवार को जब वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करें। मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में डॉक्टरों और नर्सों सहित चिकित्सा कर्मियों की भूमिका तथा जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए सभी से सतर्क रहने को कहा। वहीं, सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से छोटे-छोटे समूहों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने तथा 15 अप्रैल तक कोई विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'हम इस देश में 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।' संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बजट सत्र की अवधि कम नहीं की जाएगी और यह पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तीन अप्रैल तक चलेगा। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत एवं योगदान की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं सकारात्मक योगदान के लिए मीडिया की काफी प्रशंसा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के संदर्भ में किए गए कार्यों को सामने लाने से डॉक्टरों, नर्सों नगरपालिका कर्मियों, हवाई अड्डा कर्मियों, सीआइएसएफ एवं अग्रिम मोर्चे पर जुटे लोगों का मनोबल बढ़ता है।

रूडी के अनुसार, मोदी ने कहा कि ऐसे में हमें कोविड-19 से मुकाबला करने के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले विभिन्न लोगों का भी अभिनंदन करना चाहिए। मोदी ने कहा कि सभी स्तर पर विभिन्न प्राधिकार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चत हो कि कोविड-19 नहीं फैले। रूडी के कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि शनिवार एवं रविवार को जब वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से बताया कि मीडिया ने काफी सकारात्मक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी संसदीय दल की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में बताया।

तेजस युद्धक विमान ने मंजूरी की अंतिम उड़ान भरी

- बेंगलुरु में चालीस मिनट की सफल उड़ान के बाद एचएएल ने दी जानकारी
- एफओसी के बाद शेष 15 विमानों का निर्माण हो जाएगा शुरू

पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान ने अंतिम संचालन मंजूरी-मानक के तहत मंगलवार को बेंगलुरु में एचएएल के एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी। एएनआइ

बेंगलुरु, प्रेट्र : हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एलान किया है कि पहले हल्के युद्धक विमान तेजस ने आकाश में अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। अंतिम अभियान मंजूरी के लिए यह मानक (एसपी-21) स्तर की 40 मिनट की उड़ान थी।

सरकारी रक्षा कंपनी एचएएल की ओर से जारी बयान के अनुसार एयर कमांडर (सेवानिवृत्त) केए मुथाना तेजस युद्धक विमान के पायलट थे। एचएएल के सीएमडी आर. माधवन ने बताया कि बेंगलुरु स्थित एचएएल एयरपोर्ट से उन्होंने यह उड़ान मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे मुख्य टेस्ट फ्लाइंग (फिक्सड विंग) की प्रक्रिया के तहत की। इस उड़ान से एचएएल के एलसीए तेजस प्रोजेक्ट की टीमों के बीच गजब का तालमेल नजर आया। एयरोनाटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, सेंटर फार मिलेट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टीफिकेशन, भारतीय वायुसेना और एयरोनाटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी ने मिलकर उम्दा काम किया है। हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने ड्राइंग एप्लीकेबिल्टी लिस्ट (डीएएल) और स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की यह उपलब्धि 12 महीने के रिकार्ड टाइम में हासिल की है।

उन्होंने बताया कि इससे एफओसी (फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस) के बाद तेजस के शेष 15 विमानों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इन विमानों की आपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में की जानी है। एफओसी में हवा में ही एक विमान में दूसरे विमान से ईंधन भरा जाता है। यह बियांड विजुअल रेंज (बीवीआर) मिसाइल प्रणाली से भी लैस होता है। तेजस की यह खेप वायुसेना के दस्ते का हिस्सा बनेगी। उल्लेखनीय है कि रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस लड़ाकू विमान की खूब तारीफ की है।

राहुल बोले आर्थिक सुनामी ला सकता है कोरोना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कांग्रेस नेता ने कहा- गंभीरता की बजाय भटकाने पर ज्यादा ध्यान

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की चुनौती के साथ अर्थव्यवस्था पर इसके हो रहे गंभीर असर को लेकर सरकार को आगाह किया है। उन्होंने कहा,पहले से जारी आर्थिक चुनौतियों के दौर में कोरोना अर्थव्यवस्था के लिए सुनामी बनता नजर आ रहा है। इन से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को अपर्याप्त ठहराते हुए राहुल ने कहा कि समय रहते नहीं चेता गया तो इसकी सुनामी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी।

कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए सरकार के कदमों को लगातार अपर्याप्त बता रहे राहुल ने संसद भवन में पत्रकारों से कहा, वह पहले से कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड-19 वायरस के भारत में आने से पूर्व ही वह लगातार सरकार को आगाह करते रहे हैं कि इसके खतरों से निपटने की तैयारी शुरू कर दे। मगर सरकार सतही तौर पर इधर-उधर की बात कर यहां भी असली चुनौती से ध्यान बंटा रही है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर आर्थिक हालत को संभालने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस एहतियाती कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की बात करना और उसके लिए जरूरी कदम उठाना असली राष्ट्रवाद है, मगर इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसीलिए दुखी मन से वह कह रहे हैं कि हमारे सामने ऐसा आर्थिक संकट आने वाला है कि करोड़ों लोगों का नुकसान होगा और दुख पहुंचेगा। विडंबना है कि इस संकट पर उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। मूडीज के भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटाने के सवाल पर राहुल ने कहा, मसला रेटिंग बढ़ाने या घटाने का नहीं है। असली समस्या है कि प्रधानमंत्री का यह नजरिया बन गया है कि बाहरी लोग कैसी रेटिंग देते हैं। जहां तक उनका सवाल है, विदेशी रेटिंग की परवाह किए बिना हम अर्थव्यवस्था और अपने लोगों की ताकत पर भरोसा करें तो बेहतर होगा। हमने अपनी ताकत और लोगों के सहारे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की नीति आगे नहीं बढ़ाई तो फिर मौजूदा दौर में तबाही का सामना करना पड़ सकता है।

किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता नागरिकता संशोधन कानून : केंद्र

- सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा, सीएए को वैध बताया
- कहा, इससे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का सवाल ही नहीं है

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), 2019 किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। इसने कहा कि इससे किसी भारतीय नागरिक का कानूनी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकार प्रभावित नहीं होता है। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए इसने कहा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अधार्मिक नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों का संज्ञान लेता है और सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है। केंद्र ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने 129 पेज के हलफनामे में सीएए को वैध बताया और कहा कि इससे किसी भी प्रकार की संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का सवाल ही नहीं है।

हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि यह कानून कार्यपालिका को किसी प्रकार का मनमाना और अनियंत्रित अधिकार प्रदान नहीं करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को इस कानून के तहत विर्निदिष्ट तरीके से ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय में निदेशक बीसी जोशी ने यह हलफनामा दाखिल किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता जांचने का निश्चय किया था, लेकिन उसने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। संशोधित नागरिकता कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर, 2014 तक यहां आ गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में सौ से ज्यादा याचिकाएं दायर कर इस कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि यह कानून समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसका मकसद धार्मिक आधार पर कुछ लोगों को बाहर कर अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को नागरिकता देना है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय की इस बात से सहमति जताई थी कि आम लोगों को सीएए के उद्देश्य और सामग्री के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा था कि वे ऑडियो-विजुअल माध्यम का उपयोग कर नागरिकों को कानून के प्रति जागरूक करने पर विचार करें।

संसद प्रश्नोत्तर

पड़ोसी देशों के 25,782 अल्पसंख्यकों को दिया गया दीर्घ अवधि वीजा

- 12 मार्च तक कुल 35,79,011 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी किए गए

लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले पांच वर्षों के दौरान बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के 25,782 लोगों को दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले विदेशियों की देखभाल सामुदायिक आधार पर नहीं की जाती है। राय ने कहा कि एलटीवी पर भारत में रहने वाले ऐसे लोगों को सरकार ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी हैं। इनमें बच्चों का स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी-प्रोफेशनल संस्थानों में नामांकन शामिल है। इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

मंत्री बोले, पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को पेंशन नहीं : गृह राज्यमंत्री ने कहा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को सरकार पेंशन नहीं देने जा रही है। राय ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में कुल 2,214 एनजीओ को एफसीआरए के तहत लाइसेंस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एफसीआरए के तहत वर्ष 2017 में 1,011, वर्ष 2018 में 520 और वर्ष 2019 में 683 एनजीओ को लाइसेंस दिए गए हैं। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि 12 मार्च 2020 तक 35,79,011 भारतवंशियों को ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआइ)कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

आयकर विभाग ने इस साल जनवरी तक 1,052 करोड़ की संपत्ति जब्त की

आयकर विभाग ने इस साल जनवरी तक 1,051.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। विभाग ने 893 कंपनियों पर छापे मारे। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा,2018-19 के दौरान विभाग ने 983 कंपनियों पर छापेमारी कर 1,584.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

इतिहास में मौजूद हैं कई गोगोई प्रकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से हटते ही पहले भी बनते रहे हैं राजनीतिक पार्टी के सदस्य
- कांग्रेस और वामदल से लेकर कई नेताओं की ओर से उठाए गए हैं इस बार सवाल

यूं को राज्यसभा में अपने मनोनयन को लेकर उठे विवाद के बीच खुद पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने स्पष्ट कर दिया है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वह पूरी सच्चाई सामने रखेंगे। लेकिन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और वामदल से लेकर कई नेताओं की ओर से सीधे तौर पर इसे केंद्र सरकार और जस्टिस रंजन गोगोई के बीच आंतरिक समझौते के रूप में पेश किया जा रहा है। बहरहाल, अगर इतिहास देखा जाए तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से हटते ही किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन गए थे।

आपातकाल के दौरान तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज करके किस तरह जस्टिस एएन रे को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था, यह तो सार्वजनिक है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और फिर कांग्रेस कोटे से राज्यसभा भी पहुंचे थे। उन्होंने सिख दंगा मामले में कांग्रेस को राहत दी थी। मुहम्मद हिदायतुल्ला तो मुख्य न्यायाधीश पद के बाद उपराष्ट्रपति भी बने थे। बहरहाल, सबसे रोचक मामला जस्टिस बहरुल इस्लाम का था। इंदिरा गांधी काल में बहरुल इस्लाम राज्यसभा से इस्तीफा देकर असम हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने और मुख्य न्यायाधीश के रूप मे रिटायर हुए। वहां से रिटायरमेंट के बाद चौंकाने वाले फैसले के रूप में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया जहां उनके एक फैसले से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बिहार की तत्कालीन जगन्नाथ मिश्रा सरकार को राहत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देने के बाद वह कांग्रेस सदस्य के रूप में 1984 में राज्यसभा पहुंच गए थे। ध्यान रहे कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तीखा ट्वीट करते हुए कहा था, 'सुभाष चंद्र बोस ने कहा था- तुम मुझे खून दो मै तुम्हें आजादी दूंगा, भाजपा का कहना है- तुम मुझे वैचारिक फैसले दो, मैं तुम्हें राज्यसभा दूंगा।' कांग्रेस, वाम और दूसरे दलों के नेताओं ने सीधा आरोप लगाया कि राम मंदिर और एनआरसी पर फैसले के लिए भाजपा ने उन्हें पुरस्कृत किया है। बहरहाल इतिहास के तथ्य साफ करते हैं कि जब इस पर चर्चा छिड़ेगी तो भाजपा की ओर से कांग्रेस काल की लंबी कड़ियां गिनाई जाएंगी।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बड़ा खतरा : कुरियन जोसेफ

प्रथम पृष्ठ से आगे

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मंगलवार को कहा, वह यह देखकर चकित हैं कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखने की अपनी प्रतिबद्धता से समझौता कर लिया है। कुरियन जोसेफ भी सुप्रीम कोर्ट के उन चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश की कार्यशैली के खिलाफ 12 जनवरी, 2018 को प्रेस कांफ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि जब लोगों का विश्वास डगमगा जाता है तो ठोस बुनियाद पर निर्मित देश का संतुलन भी डगमगा जाता है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा, 'इस संतुलन को मजबूत करने और न्यायपालिका को एक दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि पूरी तरह स्वतंत्र बनाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की थी। अप्रत्याशित पहल के तहत जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी. लोकुर के साथ मैं लोगों के सामने देश को यह बताने के लिए आया था कि इस बुनियाद को खतरा था और अब मुझे लगता है कि खतरा ज्यादा बड़ा है।' जस्टिस जोसेफ ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लेने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है, पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन स्वीकार करने से आम लोगों का न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर से विश्वास निश्चित रूप से हिल गया है।'

संजय हेगड़े बोले, गलत मिसाल कायम कर रहे रंजन गोगोई : शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से अनुरोध किया है कि वह राज्यसभा का नामांकन अस्वीकार कर दें। उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआइ बहुत गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। यह फैसला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन की दीवार को खंडित कर रहा है।

राज्यसभा के लिए रंजन गोगोई के नामांकन की आलोचना करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'मोदी जी, अमित शाह जी हमारी नहीं तो अरुण जेटली की तो सुन लीजिए। क्या रिटायरमेंट के बाद जजों को अनुग्रहित करने के बारे में उन्होंने बोला और लिखा नहीं था? क्या आपको याद है?' वहीं, माकपा ने कहा कि रंजन गोगोई का नामांकन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने की बेशर्म कोशिश है। राकांपा प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि सरकार को ऐसे जजों को राज्यसभा में नामित करने से बचना चाहिए जिन्होंने संवेदनशील मामलों में फैसले सुनाए हों।

अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से 79 आतंकी घटनाएं

जी. किशन रेड्डी फाइल फोटो

अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कुल 79 आतंकी घटनाएं हुईं और 49 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पांच अगस्त 2015 से 10 मार्च 2020 तक देश के भीतर कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई।

जम्मू-कश्मीर में 450 अभी तक हिरासत में

एक अन्य सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में वर्तमान में कुल 450 लोग हिरासत में बंद हैं। इन लोगों में पत्थरबाज, उपद्रवी, अलगाववादी और कार्यकर्ता शामिल हैं। इन्हें विभिन्न जेलों में रखा गया है।

एक साल के दौरान असम के हिरासत केंद्रों में 10 की मौत

असम के छह हिरासत केंद्रों में पिछले एक साल के दौरान 10 कैदियों को मृत घोषित किया गया। गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इन छह केंद्रों में करीब 3,331 बंदी हैं जबकि 3000 लोगों को रखने की क्षमता वाले ऐसे ही हिरासत केंद्र का निर्माण जारी है।

उठाया सवाल

विधि आयोग की सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई के बारे में पूछा, रिपोर्ट के मुताबिक, समान नागरिक संहिता न जरूरी है और न ही वांछनीय

समान नागरिक संहिता पर जयराम ने सरकार से मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मंगलवार को राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश। एएनआइ

केंद्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट में विवादित समान नागरिक संहिता पर की गई सिफारिशों को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश ने मंगलवार को पूछा, 'समान नागरिक संहिता के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कदम उठाया है?'

कांग्रेस नेता ने कहा कि विधि आयोग की सिफारिश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इस मौके पर समान नागरिक संहिता न तो जरूरी है और न ही वांछनीय है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने 2018 में परिवार संबंधी कानून में सुधार पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसमें विवाह, तलाक, बच्चों का अभिभावक सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। जयराम 185 पेज के कंसल्टेशन पेपर में की गई सिफारिशों पर विस्तार से जिक्र करना चाहते थे, लेकिन शून्यकाल में समय कम होने की वजह से इस पर अलग से बहस कराने की मांग की।

श्रमिकों की छंटनी का मुद्दा उठा : शून्यकाल में ही द्रमुक के एम षणमुगम ने आर्थिक मंदी के कारण आइटी और वाहन कंपनियों में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के सदस्य विप्लव ठाकुर ने दुनिया भर में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस वायरस के कारण पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर होटलों की बुकिंग रद हो रही है।। इस बीमारी के कारण सहमे पर्यटक अपनी यात्रा और कार्यक्रम रद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए होटल उद्योग और पर्यटन काफी अहम हैं। होटल मालिक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। विप्लव ठाकुर ने कहा कि कोराना वायरस के कारण राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के मानस रंजन भूइयां ने आरोप लगाया कि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में त्रुटि के कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए हैं। उन्होंने नए सिरे से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की। बीजू जनता दल (बीजद) के सदस्य अमर पटनायक ने राज्यसभा में स्वास्थ्य क्षेत्र में अपर्याप्त खर्च किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने और प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों पर खर्च बढ़ाए जाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे है। हालांकि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना शेष है।

कह के रहेंगे माधव जोशी